

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 698
उत्तर देने की तारीख 24.07.2025

पीएम-जनमन योजना की कार्यान्वयन स्थिति

698. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

श्री के. सुधाकरन:

एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की बस्तियाँ और परिवारों को शामिल करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों की सूची क्या है;

(ख) देश भर में उक्त योजना के अंतर्गत प्रस्तावित, स्वीकृत, पूर्ण और लंबित परियोजनाओं का घटक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पीएम-जनमन के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि वर्ष वार और राज्य-वार कितनी है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): पीएम-जनमन के उद्देश्यों को 9 संबंधित (लाइन) मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत लक्षित परियोजनाओं/उपायों के ब्यौरे **अनुलग्नक-I** में दिये गये हैं। इस अभियान के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति के राज्य-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-II** में दिये गये हैं। वित्तीय प्रगति के राज्य-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-III** में दिये गये हैं।

"पीएम-जनमन योजना की कार्यान्वयन स्थिति" के संबंध में श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी, श्री के. सुधाकरन और एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा दिनांक 24.07.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 698 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

पीएम-जनमन के अंतर्गत लक्षित परियोजनाओं/उपायों के ब्यौरे

मंत्रालय का नाम	गतिविधि	मिशन लक्ष्य (2023-2026)
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकानों का प्रावधान	4.90 लाख मकान
	सड़कों को जोड़ना	8000 कि.मी सड़क
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सचल चिकित्सा इकाइयों के अनुसार सभी को शामिल करने के लिए 733 एमएमयू पर्याप्त हैं)	1000 एमएमयू (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार सभी को शामिल करने के लिए 733 एमएमयू पर्याप्त हैं)
जल शक्ति मंत्रालय	पाइप द्वारा जल आपूर्ति	19375 गाँव
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	ऑगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और संचालन	2500
शिक्षा मंत्रालय	छात्रावासों का निर्माण और संचालन	500
संचार मंत्रालय	मोबाइल टावरों की स्थापना	4543 बस्तियों को शामिल करना
विद्युत मंत्रालय	अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण	143194 आवास
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	नई सौर ऊर्जा स्कीम के तहत स्वीकृत आवास	विद्युत मंत्रालय द्वारा सभी पात्र और शामिल नहीं किए गए आवास
जनजातीय कार्य मंत्रालय	बहुउद्देशीय केंद्र	1000
	वीडीवीके की स्थापना	500

"पीएम-जनमन योजना की कार्यान्वयन स्थिति" के संबंध में श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी, श्री के. सुधाकरन और एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा दिनांक 24.07.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 698 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृत एवं कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की प्रगति के ब्यौरे (दिनांक 30.06.2025 तक)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एमओआरडी (पीएमएवाई-जी)		एमओआरडी (पीएमजीएसवाई)		एमओजेएस (जेजेएम)		एमओएचएफडब्ल्यू (एनआरएचएम)	एमओडब्ल्यूसीडी (पोषण 2.0)		एमओई (एसएसए)	
		स्वीकृत मकान	पूर्ण	स्वीकृत सड़कें (कि.मी. में)	पूर्ण (कि.मी. में)	स्वीकृत गाँव	संतुष्ट गाँव	स्वीकृत एमएमयू	स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र	संचालित आंगनवाड़ी केंद्र	स्वीकृत (संख्या)	कार्य शुरू किया गया (संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	43644	1738	612.718	1	1936	393	141	192	139	87	4
2	बिहार	985	0	0	0	33	32	0	59	49	15	0
3	छत्तीसगढ़	33113	9138	2449.11	441	1420	372	58	191	162	40	11
4	गुजरात	12489	3872	1.55	2	572	572	17	67	67	13	3
5	झारखंड	36330	3290	914.14	13	2391	478	55	495	330	35	8
6	कर्नाटक	1100	45	63.756	0	439	193	5	23	22	5	1
7	केरल	724	10	0	0	96	1	24	7	7	4	1
8	मध्य प्रदेश	183861	73458	1835	176	4802	1519	74	704	628	106	22
9	महाराष्ट्र	52000	7827	50.14	0	2764	1510	84	178	178	25	4
10	मणिपुर	2145	0	0	0	27	2	0	75	25	6	2
11	ओडिशा	41341	13426	211.14	4	1110	561	50	89	89	76	6
12	राजस्थान	22080	6041	98.69	0	337	36	6	51	51	21	4
13	तमिलनाडु	12816	2972	0	0	1370	1237	105	55	55	8	7
14	तेलंगाना	0	0	66.96	0	300	300	29	85	76	14	9
15	त्रिपुरा	17252	12710	203.11	0	251	28	6	221	141	32	14
16	उत्तर प्रदेश	145	112	0	0	7	4	2	1	1	2	0
17	उत्तराखंड	2134	1473	0	0	115	85	24	7	7	3	3
18	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	413	81	14	0	0	0	0
19	अंडमान एंड निकोबार	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
कुल योग		462159	136112	6506.314	637	18385	7406	694	2500	2027	492	99

*संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार

क्र. सं.	राज्य का नाम	एमओपी (आरडीएसएस)		एमएनआरई		एमओसी (डीओटी-यूसओएफ)		एमओटीए			
		स्वीकृत आवास	विद्युतीकृत आवास	स्वीकृत आवास	विद्युतीकृत आवास	कवरेज के लिए नियोजित बस्ती	शामिल किए गए आवास	स्वीकृत एमपीसी	एमपीसी जहां कार्य शुरू हो गया	स्वीकृत वीडिवीके	व्यवसाय शुरू हो गया
1	आंध्र प्रदेश	25054	24924	1675	175	1629	1153	125	125	73	70
2	बिहार	51	0	0	0	0	0	7	0	0	0
3	छत्तीसगढ़	7077	7124	1578	729	190	81	75	33	16	16
4	गुजरात	6626	6626	0	0	48	28	39	35	21	21
5	झारखंड	12444	3791	2342	1154	519	451	113	46	35	31
6	कर्नाटक	1615	1546	179	179	36	27	74	51	33	1
7	केरल	345	313	98	0	52	30	15	9	7	5
8	मध्य प्रदेश	29290	22772	2060	0	206	88	125	124	83	49
9	महाराष्ट्र	9216	9216	0	0	418	280	121	121	40	40
10	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	11	0	2	0
11	ओडिशा	3358	2017	0	0	459	167	74	60	43	41
12	राजस्थान	17633	15984	0	0	4	3	18	18	51	18
13	तमिलनाडु	10673	6102	0	0	164	106	60	57	37	5
14	तेलंगाना	3884	3884	326	126	99	41	73	63	25	0
15	त्रिपुरा	11692	11692	1703	0	57	54	50	47	30	27
16	उत्तर प्रदेश	195	195	0	0	5	2	5	4	5	3
17	उत्तराखंड	669	669	0	0	1	1	15	9	9	5
18	पश्चिम बंगाल	3372	3372	0	0	6	3	0	0	5	0
19	अंडमान एंड निकोबार	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
कुल योग		143194	120227	9961	2363	3894	2516	1000	802	516	332

*संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार

"पीएम-जनमन योजना की कार्यान्वयन स्थिति" के संबंध में श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी, श्री के. सुधाकरन और एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा दिनांक 24.07.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 698 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

जनजातीय कार्य मंत्रालय के उपायों के लिए पीएम-जनमन के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृति/जारी की गई निधियां*

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय				
		एमपीसी			वीडीवीके**	
		वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान जारी की गई निधियां	उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत	एसएनए शेष	स्वीकृत निधियां	जारी की गई निधियां
1	आंध्र प्रदेश	47.49	19.87	0.06	3.0755	1.53825
2	छत्तीसगढ़	8.52	0.00	6.96	1.1975	0.59875
3	गुजरात	6.03	0.00	3.54	0.525	0.2625
4	झारखंड	18.54	0.62	16.53	1.438	0.72
5	कर्नाटक	28.99	3.33	15.42	0.918	0.292
6	केरल	2.29	0.00	1.10	0.2685	0.10825
7	मध्य प्रदेश	25.99	13.47	11.78	2.545	1.27275
8	महाराष्ट्र	45.03	12.47	24.65	1.812	0.90635
9	ओडिशा	36.60	0.00	11.85	2.2365	0.8891
10	राजस्थान	6.76	0.00	1.66	4.421	2.20045
11	तमिलनाडु	25.87	10.10	5.43	1.2015	0.60075
12	तेलंगाना	16.16	0.00	4.42	0.7305	0.36525
13	त्रिपुरा	12.07	10.02	2.06	1.275	0.627
14	उत्तर प्रदेश	0.83	0.00	0.84	0.1595	0.0797
15	उत्तराखंड	7.20	0.62	0.17	0.317	0.1585
16	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.139	0
17	अंडमान एंड निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.028	0.014
18	मणिपुर	3.30	0.00	0.00	0.3	0.15
19	बिहार	2.10	0.00	0.00	0	0
कुल योग		293.77	70.5 0	106.47	22.5875	10.7836

*अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले उपायों के लिए उपयोग की गई निधियों का रिकॉर्ड संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा रखा जाता है।

** उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं
